हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 176 लखनऊ, शनिवार 21 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

उत्तर प्रदेश को दो दिन में दो बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

21 फरवरी को उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया चिप का करेंगे शिलान्यास
22 फरवरी को मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल व मेट्रो की भी देंगे सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होगा आयोजन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को डबल रफ्तार से आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश को दो बड़ी सौगातें देंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री वर्चुअली उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया चिप का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजना स्थल पर उपस्थित रहेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल व मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर रैली मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी उनके साथ रहेंगे।

उत्तर प्रदेश बनेगा देश का सेमीकंडक्टर केंद्र

उत्तर प्रदेश को देश के सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में शनिवार को ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा, जब यीडा क्षेत्र में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास होगा। यह संयुक्त उद्यम एचसीएल ग्रुप और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली शिलान्यास करेंगे जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव परियोजना स्थल पर उपस्थित रहेंगे। यीडा क्षेत्र के सेक्टर 28 में 48 एकड़ भूमि पर होने जा रहा शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है। यह देश की पहली डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट (डीडीआईसी) ओसैट (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग) सुविधा होगी, जहां चिप की उन्नत पैकेजिंग, संयोजन और परीक्षण किया जाएगा। परियोजना भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष लगभग ₹45,000 करोड़ का योगदान देने में सक्षम होगी। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 3,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सुनील शर्मा, अजीत पाल, बृजेश सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

रविवार को नमो भारत रैपिड रेल व मेट्रो करेंगे समर्पित

22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,930 करोड़ से निर्मित दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर

तक (पांच किमी.), मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी मेरठ के मोहिउद्दीनपुर रैली ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह उपहार देंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, सोमेंद्र तोमर समेत यूपी–दिल्ली के अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे।

एक घंटे से कम समय में तय होगा दिल्ली–मेरठ का सफर

नमो भारत रैपिड रेल से दिल्ली–मेरठ का सफर एक घंटे से भी कम समय में तय होगा। दिल्ली में सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच कुल 15 स्टेशन होंगे और संपूर्ण कॉरिडोर में परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। यही नहीं, 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति, प्रत्येक 10 मिनट पर ट्रेन उपलब्ध होगी। साहिबाबाद, मोदीनगर, बेगमपुल और मोदीपुरम की दिल्ली एवं गाजियाबाद से कनेक्टिविटी होने के साथ ही एक लाख निजी वाहनों की आवाजाही घटेगी। इससे कार्बन उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण में कमी आएगी।

मेट्रो से आधे घंटे में होगी 21 किमी. की यात्रा

मेट्रो के शुभारंभ के पश्चात आधे घंटे से भी कम समय में मेरठ शहर में 21 कि.मी. की यात्रा पूरी हो सकेगी। मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 12 मेट्रो स्टेशन–मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, डौरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम हैं। प्रति घंटे 135 किमी. की गति होगी। प्रत्येक 10 मिनट में मेट्रो ट्रेन उपलब्ध रहेगी।

कांग्रेस ने घुसपैठियों के लिए खोल दिए थे बॉर्डर

अब एक–एक को भेजेंगे वापस, असम में गरजे अमित शाह

बीएनई

दिसपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ आसान बनाने के लिए बॉर्डर खोल दिए थे। कछार जिले के नाथनपुर इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान देश में घुसे हर अवैध बांग्लादेशी की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेशियों के लिए बॉर्डर खोलकर घुसपैठ होने दी। उन्होंने कहा, ष्मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में जो भी अवैध रूप से देश में घुसा है, उसे वापस भेजा जाएगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का उद्घाटन

अपनी यात्रा के दौरान शाह ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर स्थित कछार जिले के नाथनपुर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP–2) के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मकसद सीमावर्ती गांवों का तेजी से विकास करना है। इस योजना के तहत गांवों में बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोकना है। शाह ने कहा कि यह प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है, जिसके जरिए भारत के सीमावर्ती गांवों को विकास का एक मजबूत केंद्र बनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के पहले चरण के अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि VVP–2 के तहत इन लाभों को और अधिक गांवों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। शाह ने दोहराया कि असम और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में बना रहेगा।

अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले से आतंकी गिरफ्तार : हथियार और गोला बारूद बरामद, बड़ी आतंकी साजिश विफल

बीएनई

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले लोंगडिंग में एक संयुक्त अभियान के दौरान एनएससीएन–आईएम के एक

आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास हथियारों और गोला–बारूद का जखीरा बरामद किया गया। इटानगर के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान असम राइफल्स, विशेष टास्क फोर्स और लोंगडिंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया था। मिली सूचनाओं के आधार पर, सुरक्षा बलों ने आज लोंगडिंग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत जेडुआ गांव के पास टिसिंग में अभियान चलाया और एनएससीएन–आईएम के एक चरमपंथी को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान स्वघोषित कैप्टन पोंगलेम वांगपान के रूप में हुई है, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के इसाक–मुइवा गुट का एक सदस्य है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक 5.56 मिमी इंसास राइफल के साथ एक मैगजीन, एक 9 मिमी पिस्तौल के साथ एक मैगजीन, 18 राउंड 5.56 मिमी कारतूस और दो राउंड 9 मिमी पिस्तौल के बरामद किए। इसी बीच, एक अलग अभियान में, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नामसाई जिले में लगभग सात लाख की कीमत के 133 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की और एक महिला को गिरफ्तार किया। इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह जब्ती मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशामुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे योगी आदित्यनाथ: डॉ. डेविड फ्रॉले

प्रख्यात अमेरिकी वैदिक विद्वान ने लखनऊ में की मुख्यमंत्री से मुलाकात
योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति पर चर्चा, बोले– नाथ परंपरा से प्रशस्त हो रही वैश्विक कल्याण की नई राह
डॉ. फ्रॉले ने योगी सरकार द्वारा अयोध्या का कायाकल्प किए जाने की सराहना की

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। अमेरिका के प्रख्यात वैदिक विद्वान डॉ. डेविड फ्रॉले ने राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से योग, आयुर्वेद व सनातन संस्कृति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रशंसक डॉ. फ्रॉले ने कहा कि योगी आदित्यनाथ राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे हैं। उन्होंने नाथ परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे वैश्विक कल्याण की नई राह प्रशस्त हो रही है। अमेरिकी विद्वान ने योगी सरकार द्वारा अयोध्या का पुरातन गौरव लौटाने की सराहना की और कहा कि अयोध्या का कायाकल्प वेदों की ओर लौटने का मार्ग है। डॉ. फ्रॉले ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ समय बिताना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात रही। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी उस नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो प्राचीन योग संस्कृति से जुड़ी है और इसे भारत में जीवंत बनाए हुए है। वे इन परंपराओं को न केवल संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर विस्तार भी दे रहे हैं। साथ ही वे शरीर, मन, समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ राजनीति का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। भारत की वे सभी परंपराएं, जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रासंगिक हैं, योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं। सीएम योगी से मिलकर प्रफुल्लित डॉ. डेविड फ्रॉले ने 'नई अयोध्या' की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या का कायाकल्प अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रभु श्रीराम का दर्शन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत सुखद अनुभव देता है। भगवान राम भारत की आत्मा के प्रतीक हैं। वे हमें सूर्यवंश से जोड़ते हैं और समस्त धार्मिक परंपराओं को एक सूत्र में पिरोते हैं। आज विश्व धीरे–धीरे अपनी

आध्यात्मिक चेतना खोता जा रहा है। ऐसे में वेद, योग, आयुर्वेद और अन्य भारतीय परंपराओं तक, सबका नवोन्मेष और पुनर्जीवन मौजूदा परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे समय में योगी जी जैसा नेतृत्व मिलना भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए वरदान है। डॉ. फ्रॉले ने कहा कि योगी जी में तेज है, क्योंकि वे 'आदित्य' हैं, सूर्य तत्व से जुड़े हैं। आत्मविद्या के लिए हम आदित्य की ओर देखते हैं और सूर्य ही योग का आधार है। योगी जी के साथ कुछ क्षण बिताना भी जीवनभर के लिए यादगार पल है। विसकॉन्सिन (अमेरिका) में एक कैथोलिक परिवार में जन्मे डॉ. डेविड फ्रॉले की गिनती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के प्रमुख विचारकों में होती है। उन्होंने करीब एक दशक तक आयुर्वेद का भी अध्ययन किया है। उन्होंने वेद, हिंदू धर्म, योग, आयुर्वेद व ज्योतिष शास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया। उसी वर्ष मुंबई में साउथ इंडियन एजुकेशन सोसायटी ने भी आयुर्वेद, योग व वैदिक ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में डॉ. फ्रॉले के उल्लेखनीय योगदान को देखते उन्हें 'नेशनल एमिनेंस अवार्ड' से सम्मानित किया था।

संक्षिप्त समाचार

एआई कंटेंट पर अनिवार्य लेबलिंग आज से लागू, सोशल मीडिया को 3 घंटे में हटाने होंगे डीपफेक पोस्ट

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने एआई से तैयार किए गए डिजिटल कंटेंट को लेकर सख्त दिशा–निर्देश लागू कर दिए हैं। 10 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये नियम 20 फरवरी से प्रभावी हो गए। अब यदि कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया जाता है, तो उस पर साफ तौर पर लेबल लगाना जरूरी होगा। साथ ही, किसी भी आपत्तिजनक या गैर–कानूनी कंटेंट की शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ 3 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। नियम लागू होने से एक दिन पहले 19 फरवरी को आयोजित एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कंटेंट पर 'ऑथेंटिसिटी लेबल' की जरूरत पर जोर दिया।

डिजिटल अरेस्ट में 7 करोड़ रुपये की उगाही करने वालों ने यूं खपाया धन, क्या है कंबोडिया–वियतनाम कनेक्शन?

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट मामले में खुलासा किया है कि साइबर अपराधियों ने सात करोड़ रुपये की राशि को बड़ी चतुराई के साथ कई बैंक खातों में जमा किया था। ये बैंक खाते, उन लोगों के थे, जिन्हें साइबर धोखाधड़ी की कोई जानकारी नहीं थी। वे अपना पैसे में बढ़ोतरी, रोजगार या लोन चाहते थे, इसलिए उन्होंने आरोपियों को अपने बैंक खाते में रुपये जमा कराने की इजाजत दे दी। आरोपियों ने अपराध की रकम को तेजी से ट्रांसफर करने के लिए एएमएमएफओआरडब्लूआरडी नामक एक एपीके एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। आरोपी अर्पित राठौर ने कंबोडिया, वियतनाम आदि के व्यक्तियों को विभिन्न फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। इसके जरिए उसने अपने बाइनेंस खाते में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी) के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। बता दें कि बाइनेंस, एक अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज है।

यहां पर व्यक्तिगत अकाउंट खोला जाता है। इस खाते के माध्यम से बिटकॉइन, एथेरियम और सैकड़ों अन्य डिजिटल संपत्तियों को खरीदने, बेचने, स्टोर करने और ट्रेड करने की सुविधा मिलती है। यह अकाउंट, डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है, जहां पर खाता धारक सुरक्षित रूप से अपनी क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। एसपी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, सीबीआई के अधिकारियों का रूप धारण करने वाले जालसाजों ने उनसे 7 करोड़ रुपये की उगाही

की थी। अपराध की रकम शुरू में मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खातों में जमा की गई थी। ईडी के मुताबिक, मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खातों को गुवाहाटी के आरोपी रूमी कलिता और कानपुर के अर्पित राठौर नियंत्रित करते थे। आरोपियों ने अपराध से प्राप्त धनराशि को व्यवस्थित तरीके से कई फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित किया। इससे उन्हें साइबर अपराध की धनराशि को छिपाने और उसका दुरुपयोग करने में सुविधा हुई।

इस धनराशि के एक हिस्से को विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से छिपाया गया। राशि को, व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग तंत्रों का उपयोग करके भारत से बाहर भेजा गया। शेष धनराशि को 2 लाख से 5 लाख रुपये की छोटी–छोटी राशियों में विभिन्न फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद बैंक खातों से तुरंत नकदी निकाल ली गई।

इस नकदी का उपयोग आभासी डिजिटल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया। कमीशन रखने के बाद इन आभासी डिजिटल संपत्तियों को विदेशी नागरिकों के खातों में जमा कर दिया गया। ये फर्जी खाते आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ऋण दिलाने या रोजगार देने के झूठे वादे करके खोले गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने ओसवाल के डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में, रूमी कलिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतानु चौधरी और उनकी फर्म मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के खिलाफ 19 फरवरी को विशेष न्यायालय पीएमएलए, जालंधर में अभियोग दायर किया है। अब तक की जांच में पता चला है कि आठ अन्य साइबर अपराधों से प्राप्त अपराध की धनराशि भी 28 अगस्त 2024 को मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खाते में जमा की गई थी। इससे पहले, ईडी द्वारा एक अस्थायी कुर्की आदेश भी जारी किया गया था, जिसके तहत 1.76 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई। इस मामले में आरोपी रूमी कलिता और आरोपी अर्पित राठौर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी, फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी नाम पर मस्जिद निर्माण रोकने की मांग ठुकराई; याचिका में दी गई दलील भी खारिज

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के बनने या उसका नाम रखने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ऐसी संरचनाएं एक क्रूर हमलावर का सम्मान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने शुक्रवार को एक थोड़ी देर सुनवाई के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि बाबर एक हिंदू–विरोधी हमलावर था। वह हिंदुओं की हत्या में शामिल था। इसलिए इसके नाम पर कोई कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद का भी जिक्र किया। कील ने कहा कि बाबर के क्रूर हिंदू–विरोधी हमलावर होने के बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है। बाबर के नाम

पर मस्जिद के निर्माण को लेकर हालिया विवाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ। टीएमसी विधायक रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। कई हिंदू संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मस्जिद के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि, भारी विरोध के कारण उन्हें टीएमसी से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी नाम नया राजनीतिक दल बनाया। फिलहाल, हुमायूं की ओर से अभी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी पर 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने इसकी नींव रखी। हुमायूं कबीर ने कहा कि निर्माण कार्य तीन साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इस ढांचे के निर्माण में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद के द्वार की ऊंचाई 14 मीटर होगी। इसकी चौड़ाई 5 मीटर होगी। अकेले द्वार के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये होगी।

तीन दिवसीय बैठक में भारत, अमेरिका के अधिकारी लेंगे हिस्सा

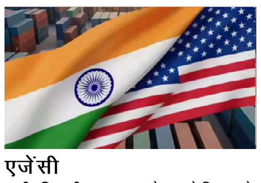

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए तीन दिवसीय बैठक 23 फरवरी से अमेरिका में शुरू होगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस महीने की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर यह घोषणा की थी कि अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा तय कर ली गई है। संयुक्त बयान में समझौते की मुख्य रूपरेखा तय की गई। अब इन बिंदुओं को एक औपचारिक कानूनी समझौते में बदला जाएगा, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। इस पर मार्च में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय और अमेरिकी दल सोमवार से अपनी तीन दिवसीय बैठक शुरू करेंगे। भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करेंगे।

संपादकीय

राहुल को मारने के खतरनाक मंसूबे

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांच महीने में दूसरी बार जान से मारने की धमकी सरेआम दी गई है। पिछले साल सितंबर में केरल के पूर्व अभाविप नेता पिंटू महादेव ने एक लाइव टीवी विमर्श में राहुल गांधी की हत्या की धमकी दी थी और अब फरवरी में फिर से राहुल गांधी को ऐसी ही एक और धमकी करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि धमकी बाकायदा वीडियो बनाकर प्रसारित की गई है। धमकी देने वाला व्यक्ति सरेआम कह रहा है कि राहुल गांधी को घर में घुसकर मारूंगा और अपना दुस्साहस भी दिखा रहा है कि मुझे जेल भेजना हो तो भेज दो। क्योंकि वो भी जानता है कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले राहुल को धमकी देने वाले पिंटू महादेव के खिलाफ भी कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, साथ ही 29 सितंबर 2025 को एक पोस्ट में लिखा था कि यह कोई आकस्मिक टिप्पणी या अतिशयोक्ति नहीं है। यह न्याय की लड़ाई में हर भारतीय के साथ खड़े नेता को दी गई एक सोची–समझी और निर्मम जान से मारने की धमकी है। राहुल को विभिन्न अवसरों पर दी गई कई धमकियों में से यह नवीनतम धमकी भाजपा के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है– इस के बाद कांग्रेस ने पूछा था कि क्या यह राहुल गांधी के खिलाफ रची जा रही कोई बड़ी, भयावह साजिश है? क्या भाजपा आपराधिक धमकियों, हिंसा और यहां तक कि जान से मारने की धमकियों की राजनीति का समर्थन करती है? क्या भाजपा विपक्ष के नेता (जो संवैधानिक पद पर हैं) और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है, जो उसके कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं? अपने बयान में कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे, वो काफी गंभीर हैं, क्या यह राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है और क्या भाजपा यानी मोदी–शाह की इसमें सहमति है। हालांकि कांग्रेस की शिकायत के बावजूद नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी देने वाले इस व्यक्ति पर कोई कठोर कार्रवाई की गई हो, ऐसी खबर ज्ञात नहीं है। बहरहाल, राहुल को मिली ताजा धमकी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे देश में एक और गोडसे तैयार करने जैसा बताया है। पवन खेड़ा ने लिखा कि आरएसएस–भाजपा का गलियारा श्गोडसे फैक्ट्रीश् है। राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ तथाकथित करणी सेना द्वारा जारी की गई धमकी कोई छिटपुट घटना नहीं है। यह एक सोची–समझी और धूर्त योजना का हिस्सा है। सबसे पहले, किरण रिजीजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिड़ला को गाली दी। फिर, विभिन्न मंचों पर भाजपा सांसदों ने एक समान बात दोहराना शुरू कर दियारू कि राहुल गांधी श्भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतराश हैं। यह विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों– विशेष रूप से राहुल गांधी– के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का एक सुनियोजित अभियान है। कट्टरपंथ का यही तरीका हैरूवे एक झूठ गढ़ते हैं, उसे बार–बार दोहराकर फैलाते हैं, राजनीतिक सत्ता के बल पर उसे वैधता प्रदान करते हैं, और तब तक उसका प्रसार करते हैं जब तक कि उनके अनुयायी घृणा और हिंसा के लिए उकसाए न जाएं। इसी तरह उस समय गोडसे का निर्माण हुआ था। इसी तरह आज एक और गोडसे को उकसाया जा रहा है। पवन खेड़ा ने पूरे हालात का सही चित्र खींचा है कि आज एक और गोडसे को उकसाया जा रहा है। क्योंकि 30 जनवरी 1948 से पहले गांधीजी के खिलाफ भी कई बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें हिंदूविरोधी दिखाया गया था, जिसके बाद दक्षिणपंथी लोगों ने गांधीजी की हत्या की साजिश रची और नाथूराम गोडसे ने इस घृणित काम को अंजाम दिया। संघ और उससे जुड़े लोग अब भी इसे हत्या न कहकर गांधी वध कहते हैं। शब्दों के इस हेरफेर में भी बड़ी चालाकी है। वध और हत्या दोनों ही किसी के प्राण लेने की क्रियाएं हैं, लेकिन वध आमतौर पर न्याय, धर्म या समाज की भलाई के लिए किसी दुष्ट या अत्याचारी को मारने को कहते हैं (जैसे– कंस वध, महिषासुर वध)) वध को नैतिक आधार दिया गया है। जबकि हत्या किसी निर्दोष, निहत्थे या सामान्य व्यक्ति को स्वार्थ, द्वेष या आपराधिक भावना से जान से मारना है। अब सोचिए किस चालाकी से गांधी वध शब्द का इस्तेमाल कर संघ गांधीजी को अत्याचारी या दुष्ट बताता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भले ही हर साल 30 जनवरी को मोदी राजघाट जाएं, लेकिन गोडसे का महिमामंडन करने वालों को आज तक सजा नहीं मिली है। याद कीजिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे की तारीफ की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी केवल इतना ही कह पाए थे कि उन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा। लेकिन इससे ज्यादा मोदी कुछ नहीं कर पाए। अब राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने वालों पर भी मोदी सरकार कोई कार्रवाई करेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल इस बार बजट सत्र में राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष मोदी सरकार पर काफी भारी पड़ा है। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब से लेकर एपस्टीन फाइल्स तक मोदी पूरी तरह घिर चुके हैं।

राशिफल

मेष :– आज का दिन शुभ और फलदायी होगा। महत्त्वपूर्ण निर्णय न लेने की सलाह है। यात्रा के योग हैं। लेखनकार्य के लिए अच्छा दिन है। महिला के साथ विवाद में न उतरें।

वृषभ :– मन को स्थिर रखने की सलाह गणेशजी देते हैं, क्योंकि अर्निणय की मनोदशा से अवसर गवां सकते हैं। प्रवास का आयोजन टाल दें। नए कार्य प्रारंभ न करें।

मिथुन :– लक्ष्मीजी की कृपा से दिन लाभदायी होगा। उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र व अपनों के साथ से दिन आनंददायी होगा। धन अधिक व्यय न करें।

कर्क :– कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें। संबंधियों से मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानहानि एवं धनहानि से बचें।

सिंह :– आज का दिन लाभदायी है। मित्रों से लाभ और पर्यटन की संभावना है। हाथ आया अवसर जा सकता है, इसलिए निर्णय टाल दें। व्यापार एवं आर्थिक लाभ के योग हैं।

कन्या :– आज दिन शुभ है। नए कार्य संपन्न होंगे। व्यापारी व नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार में लाभ व नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। पिता से लाभ होगा।

तुला :– व्यावसाय में लाभ की संभावना है ऐसा गणेशजी कहते हैं। नौकरी व व्यापार में सहकर्मियों से सहयोग नहीं मिलेगा। लंबी यात्रा का आयोजन हो सकता है। अस्वस्थ रहेंगे।

वृश्चिक :– आज शांति व सावधानीपूर्वक रूप से रहने की गणेशजी की सलाह है। नए कार्यों में असफलता के योग हैं। क्रोध पर संयम रखें। सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें।

धनु :– आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा। सहवास का आनंद मिलेगा। प्रवास, पर्यटन होगा। लेखनकार्य के दिन अनुकूल है। साझेदारी से लाभ होगा।

मकर :– व्यापार में विकास के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। ध ान के लेनदेन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में सुख–शांति का वातावरण बना रहेगा।

कुंभ :– आप की वाणी व विचारों में शीघ्र परिवर्तन होगा। बौद्धिक चर्चा में शामिल होंगे। आकस्मिक खर्च की आशंका है। पाचन न होने जैसी बीमारियों से परेशान होंगे।

मीन :– गणेशजी कहते हैं कि आप में उत्साह व स्फूर्ति की कमी होगी। परिजनों के साथ विवाद न करें। अस्वस्थ महसूस करेंगे। नौकरी में चिंता रहेगी। धन व कीर्ति की हानि न हो ध्यान रखें।

कोविड टीका और हृदयाघात : अफ़वाहों के शोर में दबता विज्ञान

—डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में कोविड महामारी के बाद यदि कोई भय सबसे तेज़ी से समाज में फैला है, तो वह हैकृकोविड टीकों और हृदयाघात के बीच कथित संबंध। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों, अधूरी जानकारियों से भरे वीडियो, टीवी स्टूडियो की उत्तेजक बहसों और कुछ गैर–जिम्मेदार बयानों ने यह धारणा बना दी है कि कोविशील्ड या कोवैक्सिन जैसे टीकों के कारण युवाओं में अचानक हृदयाघात हो रहा है। यह डर इतना गहरा हो चुका है कि कई लोग टीकों को "धीमा ज़हर" तक कहने लगे हैं। लेकिन असली प्रश्न यह हैकृक्या यह भय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, या यह केवल अफ़वाहों और भ्रम की एक लंबी श्रृंखला है? हाल के महीनों में कर्नाटक के हासन ज़िले में हुई 22 अचानक मौतों को कोविड टीकों से जोड़कर उठाए गए सवालों ने इस बहस को और हवा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेज़ी से फैलने लगा कि "गलत इंजेक्शन" के कारण युवाओं की जान जा रही है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत जांच के बाद स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि इन मौतों और कोविड टीकों के बीच कोई प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध नहीं पाया गया। यह निष्कर्ष किसी एक समिति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की शीर्ष स्वास्थ्य संस्थाओं के अध्ययनों से भी इसकी पुष्टि होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कई स्वतंत्र अध्ययनों में बार–बार यह बात सामने आई है कि भारत में उपयोग में लाए गए कोविड टीके सुरक्षित हैं। आईसीएमआर द्वारा 19 राज्यों के 47 बड़े अस्पतालों में किए गए एक बहु–केंद्र अध्ययन में अचानक हुई मौतों के कारणों का विश्लेषण किया गया। नतीजे स्पष्ट थेकृलगभग 85 प्रतिशत मामलों में मृत्यु का कारण पहले से मौजूद हृदय धमनियों का रोग था, जिसमें धमनियों में वसा की परत (प्लाक) जमा हो चुकी थी। शेष मामलों में आनुवंशिक कारण, अस्वस्थ जीवनशैली, अत्यधिक मानसिक तनाव, मोटापा, धूम्रपान और कोविड संक्रमण के बाद के प्रभाव जिम्मेदार पाए गए। टीकों का कोई प्रत्यक्ष या निर्णायक संबंध सामने नहीं आया। यह सच है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अदालत में यह स्वीकार किया कि उसके टीके से एक अत्यंत दुर्लभ स्थितिकृरक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स की कमी का लक्षण–समूहकृहो सकता है। लेकिन यह स्थिति लाखों में कुछ गिने–चुने मामलों में देखी गई और वह भी टीका लगने के शुरुआती हफ्तों में। चिकित्सकीय दृष्टि से यह स्थिति और हृदयाघात दो अलग–अलग रोग प्रक्रियाएं हैं। इन दोनों को एक ही तराजू पर तौलना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है, बल्कि जनता को गुमराह करने वाला भी है। वास्तविकता यह है कि कोविड संक्रमण स्वयं हृदय के लिए कहीं अधिक घातक सिद्ध हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सहित कई देशों में हुए अध्ययनों के अनुसार, कोविड से संक्रमित व्यक्ति में हृदयाघात, मस्तिष्काघात और हृदय विफलता का जोखिम दो से तीन गुना तक बढ़ गया था। यह वायरस शरीर में व्यापक सूजन उत्पन्न करता है, जो हृदय की मांसपेशियों और रक्त नलिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। पहली और दूसरी लहर में ऐसे असंख्य मामले सामने आए, जहां अपेक्षाकृत युवा और पहले स्वस्थ दिखने वाले लोगों को भी गंभीर हृदय समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में टीकों ने जोखिम को कम करने में सुरक्षा कवच की भूमिका निभाई। फिर यह सवाल उठता है कि महामारी के बाद अचानक मौतों और हृदयाघात की घटनाएं क्यों बढ़ती दिखाई दे रही हैं? विशेषज्ञों का उत्तर अपेक्षाकृत स्पष्ट हैकृमहामारी के बाद की बदली हुई जीवनशैली। लंबे लॉकडाउन के दौरान शारीरिक गतिविधि में भारी कमी आई, वजन बढ़ा, मानसिक तनाव और अवसाद बढ़े, नींद का चक्र बिगड़ा और जंक फूड की खपत में वृद्धि हुई। इसके अलावा, कोविड संक्रमण के बाद लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन, थकान और सांस संबंधी समस्याएं भी हृदय जोखिम को बढ़ाती हैं। इन जटिल और वास्तविक कारणों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय सारा दोष टीकों पर मढ़ देना आसान है, लेकिन यह वैज्ञानिक सच्चाई से कोसों दूर है। यह बहस केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक जिम्मेदारी से भी गहराई से जुड़ी है। जब अफ़वाहें फैलती हैं, तो टीकाकरण

के प्रति हिचकिचाहट बढ़ती है। भविष्य में यदि किसी नई महामारी का सामना करना पड़ा और लोग टीकों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम कहीं अधिक घातक हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि पोलियो, चेचक और खसरा जैसी बीमारियों से मानवता की लड़ाई में टीकों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। कोविड टीके भी उसी वैज्ञानिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ मीडिया मंचों और सोशल मीडिया के प्रभावशाली चेहरों ने टीआरपी और लोकप्रियता के लिए "टीका जानलेवा है" जैसे शब्दों का लापरवाही से प्रयोग किया। आधे–अधूरे तथ्यों को सनसनीखेज ढंग से पेश किया गया, जबकि पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट शायद ही कभी चर्चा में आई। नतीजा यह हुआ कि डर ने तर्क पर और अफ़वाह ने विज्ञान पर बढ़त बना ली। सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस भ्रम को सक्रिय रूप से दूर करें। एम्स और आईसीएमआर जैसी संस्थाओं के तथ्य–आधारित निष्कर्ष केवल वेबसाइटों या प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें गांव–गांव तक पहुंचाया जाए। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर वैज्ञानिक जानकारी का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य साक्षरता कम है। राजनीतिक नेतृत्व को भी संयम बरतना होगाकृबिना वैज्ञानिक आधार के दिए गए बयान जनविश्वास को कमजोर करते हैं और स्वास्थ्य नीतियों को नुकसान पहुंचाते हैं। "टीके को उलटने" या "डिटॉक्स" जैसी मांगें पूरी तरह अवैज्ञानिक हैं। आधुनिक चिकित्सा में वर्षों बाद किसी टीके को निष्प्रभावी करने का कोई सिद्धांत मौजूद नहीं है। इसके बजाय आवश्यकता एक व्यापक हृदय स्वास्थ्य अभियान की हैकृनियमित प्रारंभिक जांच, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की निगरानी, संतुलित आहार, योग और नियमित व्यायाम को जनआंदोलन का रूप देना। हृदयाघात से बचाव का वास्तविक मार्ग यही है। आज के डिजिटल युग में अफ़वाहें बिजली की गति से फैलती हैं, जबकि सत्य अपेक्षाकृत धीमी चाल से आगे बढ़ता है। फिर भी, दीर्घकाल में विज्ञान का मार्ग ही टिकाऊ साबित होता है। एम्स और आईसीएमआर के अध्ययनों का निष्कर्ष एक स्वर में यही कहता है–कोविड टीके सुरक्षित हैं और अचानक मौतों का उनसे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। टीके मित्र हैं, शत्रु नहीं। भारत ने कोविड जैसी अभूतपूर्व महामारी का सामना कर सामूहिक प्रयासों से विजय प्राप्त की है। अब अगली चुनौती अफ़वाहों, डर और साजिशी सिद्धांतों से निपटने की है। हृदयाघात रोकने का सबसे प्रभावी "टीका" जागरूकता हैकृवैज्ञानिक सोच, सही जानकारी और जिम्मेदार संवाद। टीकों को बदनाम कर हम न केवल विज्ञान का अपमान करते हैं, बल्कि अपने भविष्य के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालते हैं। समय आ गया है कि हम डर नहीं, आंकड़ों पर भरोसा करें और मिथकों के बजाय चिकित्सा विज्ञान को अपनाएं।

शिक्षण संस्थानों में फूहड़ मनोरंजन : शिक्षा और मर्यादा पर बढ़ता राष्ट्रीय प्रश्न

डीजे संस्कृति और अशोभनीय प्रस्तुतियों के बीच बच्चों के संस्कार, अनुशासन और शिक्षा के मूल उद्देश्य पर गंभीर चिंता

—डॉ. प्रियंका सौरभ

विद्यालय किसी भी राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करते हैं। यही वे स्थान हैं जहाँ से समाज की दिशा तय होती है और आने वाली पीढ़ियों के विचार, मूल्य तथा व्यवहार गढ़े जाते हैं। एक सभ्य समाज की पहचान उसके विद्यालयों से होती है, क्योंकि यहीं बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुशासन, नैतिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। ऐसे में यदि विद्यालय परिसरों में अशोभनीय गीतों पर नृत्य, फूहड़ मनोरंजन और मर्यादा–विहीन प्रस्तुतियाँ सामने आती हैं, तो यह केवल किसी एक संस्था की चूक नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे दृश्य सामने आए हैं, जहाँ विद्यालयों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ऐसे गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनका शिक्षा और संस्कार से कोई संबंध नहीं है। ये घटनाएँ यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम विद्यालयों को भी उसी बाज़ारू संस्कृति के हवाले कर रहे हैं, जिसने मनोरंजन को मर्यादा से ऊपर रख दिया है? क्या बच्चों की मासूम मानसिकता को हम अनजाने में ऐसे प्रभावों के हवाले कर रहे हैं, जिनका दीर्घकालिक असर उनके चरित्र और सोच पर पड़ सकता है? आज यह सत्य है कि डीजे संस्कृति, सोशल मीडिया और त्वरित लोकप्रियता की दौड़ ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। गीतों और मनोरंजन की

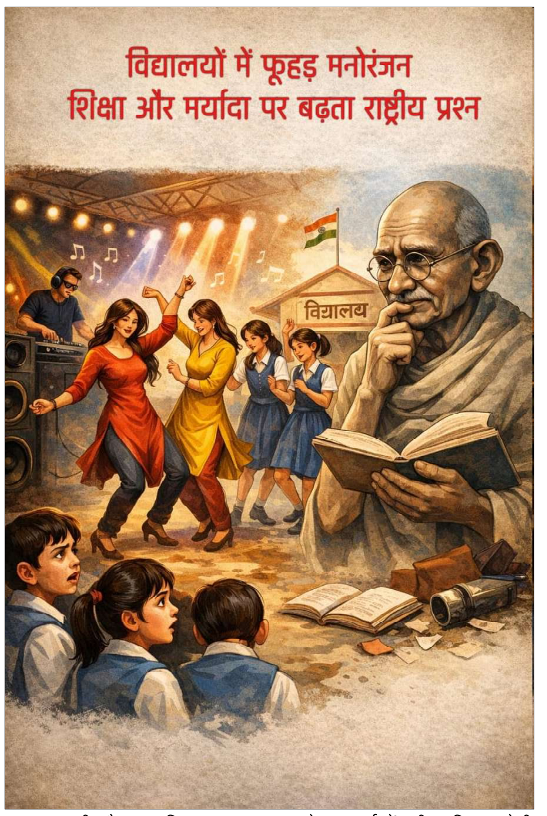

भाषा बदली है, प्रस्तुति का स्तर बदला है और 'वायरल' होने की होड़ ने विवेक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन विद्यालय कोई सार्वजनिक मंच या मनोरंजन स्थल नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यदि विद्यालय ही इस भेद को मिटाने लगें, तो बच्चों के मन में नैतिक सीमाओं की समझ कैसे विकसित होगी? इस पूरे प्रश्न का एक पक्ष यह भी है कि कई बार ऐसे कार्यक्रमों में बाहरी डीजे या आयोजनकर्ताओं की भूमिका होती है। संभव है कि किसी विद्यालय में ऐसा संगीत बिना पूर्व योजना के बज गया हो या बच्चों ने उत्साह में कोई अनुचित गीत चुन लिया हो। परंतु ऐसे हर परिदृश्य में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की होती है। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाने वाले कर्मचारी नहीं होते; वे आदर्श, अनुशासन और मर्यादा के जीवंत उदाहरण होते हैं। उनकी चुप्पी या लापरवाही बच्चों के लिए मौन स्वीकृति बन जाती है। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को सकारात्मक दिशा देना होता है। नृत्य, संगीत और नाटक बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनकी प्रतिभा को मंच देते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। लेकिन जब यही मंच फूहड़ता का माध्यम बन जाए, तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकनृत्य, देशभक्ति गीत, शास्त्रीय या सुगम संगीत, प्रेरक नाटककृये सब न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। इसके विपरीत, अश्लीलता आधारित प्रस्तुतियाँ केवल क्षणिक तालियाँ तो बटोर सकती हैं, पर वे किसी भी तरह से बच्चों के व्यक्तित्व को समृद्ध नहीं करतीं। यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज और अभिभावकों की भूमिका क्या है। आज कई बार अभिभावक भी विद्यालयों से केवल परिणाम और प्रतियोगिता की अपेक्षा रखते हैं, जबकि मूल्य–आधारित शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। यदि किसी विद्यालय में ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो केवल शिक्षकों या प्रशासन को दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं। समाज को भी यह तय करना होगा कि वह अपने बच्चों को किस तरह का वातावरण देना चाहता है। क्या हम चाहते हैं कि विद्यालय भी उसी संस्कृति को अपनाएँ, जो टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर परोसी जा रही है, या हम उनसे कुछ बेहतर, कुछ अधिक जिम्मेदार अपेक्षा रखते हैं? दूसरी ओर, यह भी आवश्यक है कि हर घटना पर प्रतिक्रिया संतुलित हो। किसी एक चूक के आधार पर पूरे शिक्षक समुदाय को कठघरे में खड़ा करना या कठोर दंड की माँग करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। शिक्षक भी इंसान हैं और उनसे भी भूल हो सकती है। यदि कोई घटना पहली बार हुई है और उसमें दुर्भावना नहीं थी, तो सुधारात्मक चेतावनी, स्पष्ट दिशा–निर्देश और संवेदनशील प्रशिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन यदि ऐसी गतिविधियाँ बार–बार हों, या जानबूझकर मर्यादा को तोड़ा जाए, तो सख्त कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि अनुशासन की मर्यादा बनी रहे। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट और एकरूप दिशा–निर्देश हों। ये दिशा–निर्देश केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका ईमानदारी से पालन हो। कार्यक्रमों की पूर्व स्वीकृति, गीतों और प्रस्तुतियों की समीक्षा, वेशभूषा की मर्यादा और मंच संचालन की जिम्मेदारीकृइन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। साथ ही शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण भी आवश्यक है, ताकि वे बदलते सामाजिक प्रभावों को समझते हुए बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नैतिकता और संस्कृति का अर्थ कठोरता या रचनात्मकता का दमन नहीं है। बच्चों को आधुनिकता से काटना समाधान नहीं, बल्कि उन्हें विवेक के साथ आधुनिकता को अपनाना सिखाना अधिक आवश्यक है। विद्यालयों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जहाँ बच्चे खुलकर अपनी प्रतिभा दिखा सकें, पर साथ ही यह भी समझें कि हर मंच की अपनी मर्यादा होती है। स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन ही स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था की पहचान है। यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह मुद्दा केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं है। यह उस सामाजिक दिशा का प्रतिबिंब है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जब समाज में फूहड़ता सामान्य होती जाती है, तो उसका असर संस्थानों पर भी पड़ता है। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल नियमों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से भी जुड़ा है। मीडिया, मनोरंजन उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्मकृसभी की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों और युवाओं के लिए जिम्मेदार सामग्री प्रस्तुत करें। भारत जैसे विविधता और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध देश में विद्यालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार सृजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक निरंतरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की वाहक है। यदि विद्यालयों में ही मर्यादा और संस्कार कमजोर पड़ने लगें, तो इसका असर केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे–धीरे समाज के ताने–बाने को भी प्रभावित करेगा। अंततः, यह आवश्यक है कि हम इस विषय को न तो अतिशयोक्ति में बदलें और न ही हल्के में लें। यह समय आत्ममंथन का है–शिक्षकों के लिए, प्रशासन के लिए, अभिभावकों के लिए और समाज के लिए। विद्यालयों को फिर से उस स्थान के रूप में स्थापित करना होगा, जहाँ ज्ञान के साथ–साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। जहाँ मनोरंजन हो, पर मर्यादा के साथ; जहाँ स्वतंत्रता हो, पर जिम्मेदारी के साथ। विद्यालय वास्तव में मंदिर हैंकृऐसे मंदिर जहाँ भविष्य की पीढ़ियाँ गढ़ी जाती हैं। इन मंदिरों की गरिमा बनाए रखना किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा पाए, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक संतुलित, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित कर सकेंगे।

आखिर जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर कैसे पाएंगे काबू?

दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने वाला जनतांत्रिक भारत आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली श्ब्रितानीश व श्मुगलियाश सियासत के चक्रब्यूह में फंसा पड़ा है। इससे श्सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाश जैसी उसकी उदात्त सोच भी कठघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है। यहां की प्रतिभाशाली और प्रभुत्ववाली सामान्य जातियों (सवर्णों) के खिलाफ देश में जो लक्षित पूर्वाग्रही राजनीति कथित दलित–ओबीसी नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे देश व समाज के सामने विभिन्न नैतिक व वैधानिक सवाल उठ खड़े हुए हैं! हैरत की बात है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे लगाए जाते हैं। कहीं जाति, कहीं धर्म और कहीं भाषा–क्षेत्र के नाम पर लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। वहीं कहीं सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण और साम्प्रदायिक सोच आधारित अल्पसंख्यकवाद के अव्यवहारिक पहलुओं को हवा देकर आमलोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आलम यह है कि ऐसे करने वाले नेता, उनके हमकदम मस्त हैं, जबकि आमलोग त्रस्त हैं। हद तो यह कि हमारे संविधान के संरक्षक अनर्गल दलीलें देकर मानवता की गला घोंट रहे हैं, जबकि यही प्रवृत्ति कतिपय संविधान निर्माताओं में भी दिखी थी। वहीं आज के कथित रखवाले जन्मांध श्धृतराष्ट्रश की भूमिका निभा रहे हैं।इनके जैसे ही नेताओं की खामोशी से जहां 1947 में साम्प्रदायिक विभाजन हुआ, वहीं इनके षडयंत्र से आजादी के बाद से ही जातीय, क्षेत्रीय व नवसंप्रदायिक विभाजन की प्रवृत्ति हावी होती दिख रही है, जो आज भी जारी है। ऐसे में एक और महाभारत छिड़ना तय है। पुनः विभाजन होना तय है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी महाभारत होता है तो संख्याबल पर बुद्धिबल ही भारी पड़ती है और आगे भी यही होगा। कहना न होगा कि कोई भी लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व की बुनियाद पर मजबूत होता है, लेकिन जब बहुमत की सियासी शरारत शुरू हो जाए और वामपंथियों के वर्गवादी राजनीति को मात देने के लिए पूंजीवादी प्रभाव वश जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की सियासत तेज हो जाए तो देर सबेर राष्ट्र राज्य का बिखरना तय होता है। इसलिए इनसे जुड़े राजनीतिक हथकंडों और उन्हें शह देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को यदि समय रहते ही नहीं बदला गया तो बाद में इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होगा! ऐसा इसलिए कि जातिवादी कैंसर, सांप्रदायिक एड्स और क्षेत्रवादी तपेदिक (टीबी) से शांतिप्रिय व सहनशील भारतीय समाज सदियों से ग्रसित है, लेकिन बीती सदी में इन्हें एक कानूनी स्वरूप देकर स्थिति को जटिल चुनौती बना दी गई है। किसी समूह के इतिहास को साक्षी मानकर उनके वर्तमान को रौंदने की जो सियासी प्रवृत्ति भारत में हावी है, उससे सामान्य व कथित सवर्ण जातियों में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए समावेशी संवैधानिक प्रावधानों, हिंसा–प्रतिहिंसा पर समान कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता के संयोजन से ही अब इस जटिल स्थिति से निबटना संभव है, लेकिन हमारी सियासी सोच इसके विपरीत है। वह आज भी विदेशी फूट डालो, शासन करो पर केंद्रित है। लिहाजा, कतिपय कानूनी उपाय अपेक्षित हैं। पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नेताओं के भाषणों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, तथा प्च्ब की धारा 153।

अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18,000, अनुदेशकों को 17,000 रुपये मिलेगा मानदेय: योगी

जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं हैं, वहां 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था : सीएम योगी
सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा, गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए की जा रही विशेष व्यवस्था
स्कूल सुरक्षा ऑडिट के बाद अनुरक्षण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये की घोषणा: सीएम योगी
शिक्षकों और कार्मिकों के आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी: मुख्यमंत्री

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। विधानसभा में बजट 2026–27 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों और नई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तीकरण, शिक्षक कल्याण और छात्र सुविधाओं को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक, शोध और कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को ज्ञान और नवाचार की अग्रणी शक्ति बनाना है। इस बजट में बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं हैं, वहां इनकी स्थापना के लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बेसिक शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहाकि पूर्व की तुलना में अब गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ड्रॉपआउट रेट में कमी आई है और कंपोजिट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मिशन निपुण एवं डिजिटल एजुकेशन जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। कंपोजिट विद्यालयों के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था विशेष रूप से गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्कूल सुरक्षा ऑडिट के बाद अनुरक्षण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये, सीएम कंपोजिट विद्यालयों के लिए 2,382 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों और कार्मिकों के आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। शिक्षामित्रों के मानदेय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में 3,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था। अब अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये तथा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया गया है। बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपये से सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, कौशल, शोध और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल दिया गया है। नैक मूल्यांकन में प्रदेश के छह राज्य विश्वविद्यालयों को A++ रैंकिंग प्राप्त हुई है। नैक मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 95 से बढ़कर 158 हो गई है। एनआईआरएफ रैंकिंग में संस्थानों की संख्या 32 से बढ़कर 158 हो गई है। पेटेंट फाइलिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पूर्व में संख्या अत्यंत कम थी, वहीं वर्तमान में 5,677 पेटेंट फाइल किए गए हैं और लगभग 350 स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने विभिन्न मंडलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, जिनमें सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडल शामिल हैं। निजी विश्वविद्यालयों के लिए पारदर्शी नीति लागू की गई है। नियमों के उल्लंघन पर दो विश्वविद्यालयों की मान्यता निरस्त भी की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कैंपस की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन, सीएम विद्यालक्ष्मी योजना, चेवनिंग स्कॉलरशिप, एआई सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम, स्टेम हॉस्टल योजना (बालिकाओं हेतु) और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार ने विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय हेतु बजट में पृथक धनराशि का भी प्रावधान किया है।

बिजलीकर्मियों का थाने पर प्रदर्शन, पावर हाउस में घुसकर महिला ने मारे थे थप्पड़

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पावर हाउस में घुसकर बिजलीकर्मियों को थप्पड़ मारने की घटना के बाद कर्मी आक्रोशित हैं। बुधवार को एक महिला ग्राहक ने विकासनगर सेक्टर–14 पावर हाउस पर बवाल मचाया था। उसने समस्या की शिकायत की तो उससे कर्मियों ने बिजली बिल डिटेल मांग ली थी। इसी पर गुस्साई महिला ने वहां पहुंचकर थप्पड़ मारे थे। उसके बाद आज, शुक्रवार को दर्जनों बिजलीकर्मियों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वे पावर हाउस से हाथों में न्याय दो लिखी तख्तियां लेकर विकासनगर थाने पहुंचे। यहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। उनका कहना है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कर्मचारी थाने के सामने नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने सख्ती बरती। इसके बाद कर्मचारियों ने नारा लगाना बंद कर दिया और शांत हो गए। कर्मचारियों ने कहा कि जिन लोगों ने उनपर हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारियों को थाने पर बुलाकर ही पूछताछ की जा रही है। कर्मचारियों ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के बाद में मनोबल गिर गया है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बुधवार को विकासनगर सेक्टर–14 स्थित पावर हाउस का वीडियो सामने आया था। आरोप है

कि विकासनगर सेक्टर–14 निवासी महिला ने कंट्रोल रूम में बिजली नहीं आने की शिकायत की थी। जब उनसे कनेक्शन संख्या बताने का अनुरोध किया गया तो महिला भड़क गई। गुस्से में फोन काट दिया। इसके कुछ देर बाद एक लड़के के साथ पावर हाउस पहुंची। कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज की। इस दौरान विकासनगर सेक्टर– 14 की रहने वाली महिला ने स्थानीय पावर हाउस स्थित कंट्रोल रूम पर बुधवार दोपहर 2.10 बजे शिकायत की। कहा कि मकान सं–14/115 में बिजली नहीं आ रही है। जब बिजली कर्मचारियों ने उनसे जमा बिल की जानकारी की और कनेक्शन संख्या बताने का अनुरोध किया तो महिला ने गुस्से में फोन काट दिया। कुछ देर बाद महिला एक अन्य व्यक्ति के साथ पावर हाउस पहुंची। वहां घुसते ही उसने बिजली कर्मचारी अनूप कुमार के साथ गाली–गलौच शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी देने लगी। कंट्रोल रूम में रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। बिजली कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी इस बीच कर्मचारियों ने मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो महिला ने उनका मोबाइल छीन लिया। बिजली कर्मचारी हरीश यादव का गला दबा दिया। थप्पड़ भी मारे। डॉयल–112 पर फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मारपीट में उपकेंद्र पर कार्यरत हरीश यादव, आकाश कन्नौजिया, अनूप कुमार और रजनीश यादव को चोट आई है।

उप मुख्यमंत्री ने की गृह, राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा

शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए : केशव

संवाददाता

लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज विधान भवन में चल रहे बजट सत्र–2026 की कार्यवाही से पूर्व विधानसभा कक्ष संख्या–77 में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, न्याय विभाग एवं गृह विभाग के कार्यों की प्रगति, जनहित से जुड़े मामलों तथा कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे।बैठक में अफसरों निर्देश दिये कि कार्यों का सही तरीके से किया जाय,किसी स्तर पर लापरवाही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने राजस्व विभाग को भूमि विवादों, नामांतरण, वरासत एवं ऑनलाइन सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये। ग्राम विकास विभाग को ग्रामीण सड़क,

आवास, शौचालय एवं आजीविका योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा।न्याय विभाग को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी एवं समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिया। उन्होंने गृह विभाग को कानून–व्यवस्था मजबूत रखने, महिला सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिया।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सरकार की पहचान है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि बजट सत्र के दौरान प्राप्त जनप्रतिनिधियों की शिकायतों एवं सुझावों पर तत्काल कार्यवाही की जाए।बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूर्ण करने पर बल दिया।

गार्मियों में सबको बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु व्यापक तैयारियॉं शुरू

मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता रहे, इसके लिये कारपोरेशन ने बनायी रणनीति
बनारस नोएडा एवं कानपुर में आर.डी.एस.एस एवं स्कॉडा के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। आगामी गर्मियों में प्रदेश को मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित हो इसकी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने वृहद स्तर पर तैयारी शुरू की है। आज शक्ति भवन में इस सन्दर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा0 आशीष गोयल ने निर्देशित किया कि आगामी गर्मी के महीनों में मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध रहे इसकी अभी से बेहतर प्लानिंग सुनिश्चित कर लें। जिससे गार्मियों में। सबको बेहतर विद्युत प्राप्त हो। उन्होंने कहाकि हर वर्ष गर्मी में विद्युत आपूर्ति के नये रिकार्ड बनते हैं। इस वर्ष भी मांग बढ़ेगी इसलिये पूरी तैयारी करके रखी जाये। पिछले वर्ष जून 2025 में मांग एवं आपूर्ति का रिकार्ड लगभग 32068 मेगावाट का बना था। इस वर्ष इसके बढ़ने की संभावना है। इसलिये बैंकिंग एवं अनुबन्ध आदि के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये। बनारस में

आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत विद्युत के ढ़ाचागत विकास के कार्यों में और तेजी लाने के लिये कार्यदायी संस्था को सख्त चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये। अध्यक्ष ने कहाकि कार्यो में विलंब बिलकुल भी बरदास्त नहीं की जायेगी। जो भी कार्य हो रहे हैं वे निश्चित समय पर पूर्ण हों यह सुनिश्चित करना है। विकास कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता भी निर्धारित मानक के अनुरूप हो। बनारस में कार्यों में हो रहे विलम्ब पर अध्यक्ष ने कहाकि कार्यदायी संस्था को टर्मिनेशन हेतु चेतावनी जारी की जाये। एक महीने में यदि कार्य में प्रगति नहीं आयेगी तो आगे कार्यवाई की जायेगी। नोएडा एवं कानपुर में आर0डी0एस0एस0 एवं स्काडा के कार्यों में विलंब को देखते हुये यहॉ कार्य कर रही संस्थाओं को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिये गये। इन नगरों में भूमिगत केबिलिंग के साथ विद्युत व्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत केबिल, कन्डक्टर, लाइने एवं ट्रांसफार्मर आदि की आवश्यकतानुसार क्षमतावृद्धि, अनुरक्षण एवं स्थापित किया जा रहा है। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप लोग रेग्यूलर समीक्षा करके यह सुनिश्चित करिये कि आर.डी.एस.एस और स्कॉडा के अन्तर्गत हो रहे कार्य निर्धारण समय पर पूर्ण हो जाये। उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो। इसमें शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाई करें। अध्यक्ष ने आरडीएसएस एवं स्काडा परियोजनाओं को विद्युत वितरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण की रीढ़ बताते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, भूमिगत केबिलिंग, क्षमता वृद्धि, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली तथा रियल–टाइम मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि तकूनीकी हानियों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। शक्ति भवन में सम्पन्न इस बैठक में प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार सहित प्रदेशभर की कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित वितरण निगमों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एमकेआईटीएम और इग्नू की संयुक्त पहल

तीन सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश जारी
सीएफओ, सीएफबीओ, सीएचओ और पीजीडीएचओ में नामांकन का अवसर
उत्तर प्रदेश को पर्यटन–आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता : जयवीर

संवाददाता

लखनऊ। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट एमकेआईटीएम ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के सहयोग से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड में तीन सर्टिफिकेट तथा पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। यह पहल उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो लचीले अध्ययन विकल्प के साथ पर्यटन उद्योग में पेशेवर पहचान बनाना चाहते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि एमकेआईटीएम द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र सैद्धांतिक शिक्षा के साथ–साथ औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो नियमित कक्षाओं में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं। एमकेआईटीएम छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहा है। इच्छुक छात्र हॉस्टल की निर्धारित फीस का भुगतान कर निवास तथा नियमित कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं।श एमकेआईटीएम और इग्नू द्वारा संचालित तीनों सर्टिफिकेट कोर्सों– सर्टिफिकेट इन फरंट ऑफिस ऑपरेशन सीएफओ सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन सीएफबीओ और सर्टिफिकेट इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन सीएचओ के लिए योग्यता 102 बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। तीनों सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने की अवधि के हैं, जिनके लिए 18 क्रेडिट निर्धारित हैं। सर्टिफिकेट कोर्स की फीस 3,000 रुपए निर्धारित की गई है, 400 रुपए पंजीकरण शुल्क देय होगा। छात्रों को दो महीने थ्योरी और चार महीने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाएगी। एमकेआईटीएम और इग्नू द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशन्स पीजीडीएचओ एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। यह होटल इंडस्ट्री में संचालन और प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर ली है। कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके लिए 48 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। यह पाठ्यक्रम

छात्रों को होटल उद्योग में विभिन्न प्रकार के कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। पीजीडीएचओ पाठ्यक्रम के लिए 9,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है, जिसके साथ 400 रुपए पंजीकरण शुल्क अलग से देय होगा। पीजी डिप्लोमा कोर्स के दौरान छात्रों को चार महीने थ्योरी और आठ महीने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग व इंटर्नशिप कराई जाएगी।अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि एमकेआईटीएम द्वारा इग्नू के सहयोग से प्रारंभ किए गए ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर हैं, जो लचीली अध्ययन व्यवस्था के साथ आतिथ्य और होटल उद्योग में पेशेवर पहचान बनाना चाहते हैं। 2025 में हुए समझौते के तहत इच्छुक छात्र अब इग्नू संचालित टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के कोर्स एमकेआईटीएम से भी कर सकते हैं।

लखनऊ-चित्रकूट नई बस सेवा की शुरुआत

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह का इंतजार करते–करते मंत्री आशीष पटेल थक गए। 20 मिनट तक उन्होंने सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार किया। थकने पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पर स्थित अपने घर से कुर्सी मंगवाई। कुर्सी पेड़ के नीचे रखकर बैठ गए। एक घंटे बाद दया शंकर सिंह पहुंचे। उनके देर से पहुंचने पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा जिसका दिल बड़ा होता है, उनके पास लोग बड़े होते हैं। जब लोग बड़े होते हैं तो देर से आना स्वाभाविक है। दरअसल, आज सुबह 10 बजे माल एवेन्यू–1 से लखनऊ–चित्रकूट नई बस सेवा की शुरुआत होनी थी। मंत्री दयाशंकर और आशीष हरी झंडी दिखाकर बस को चित्रकूट (हनुमानगंज) के लिए रवाना करना था। आशीष पटेल समय पर पहुंचे, लेकिन दयाशंकर सिंह 11 बजे पहुंचे। फिर दोनों ने बस सेवा की शुरुआत की। मंत्री दया शंकर सिंह के कार्यक्रम में लेट पहुंचने का सिलसिला नया नहीं है। उनके देर से पहुंचने को लेकर सीएम योगी भी चुटकी ले चुके हैं। कहा था–मंत्रीजी आज टाइम पर आ गए, लगता है बसों की टाइमिंग भी ठीक कर देंगे। मंत्री आशीष पटेल ने कहा परिवहन मंत्रीजी का ह्रदय बहुत बड़ा है। जब इनके पास कोई मांगने जाता है तो उसे ये देते जरूर हैं। मेरी मांग परिवहन मंत्रीजी ने पूरी की। परिवहन

मंत्री के देर से आने पर कहा जिनका दिल बड़ा होता है, उनके पास लोग बड़े होते हैं। जब लोग बड़े होते हैं तो उनका विलंब से आना स्वाभाविक है। ये इनका स्वभाव है कि किसी को मना नहीं कर पाते हैं। यह नई बस लखनऊ से चित्रकूट के बीच ऊंचाहार, लेहदरी गंगा पुल, सिराथू, राजापुर से होकर चित्रकूट के हनुमानगंज पहुंचेगी। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों, लखनऊ से चित्रकूट दर्शन के लिए जाने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी। हनुमानगंज, प्रसिद्ध स्थल हनुमानधारा से सटे गांव का नाम है। मंत्री आशीष पटेल के अनुसार, जहां तक (हनुमानगंज) यह बस जाएगी, वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। जहां–जहां बस चलेगी, वे भी पिछड़े इलाके हैं। बस सिराथू के बाद धाता जाएगी। वहां से राजापुर और राजापुर से कर्वी की ओर न जाकर लालता रोड (मऊ) की तरफ से हनुमानगंज पहुंचेगी। चित्रकूट धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। इस नई बस सेवा से श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। परिवहन विभाग के अनुसार, यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि क्षेत्रीय संपर्क और अधिक सशक्त हो सके।

राज्य मंत्री ने राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025–26 का किया शुभारंभ

संवाददाता

लखनऊ। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025–26 का शुभारंभ शुक्रवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलन, ध्वजारोहण, मार्च पास्ट की सलामी और प्रतिभागियों के शपथ ग्रहण के साथ प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विभाग का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के साथ युवाओं को खेलों से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आईटीआई संस्थानों में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी शारीरिक रूप से सशक्त और मानसिक रूप से आत्मविश्वासी बन सकें। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने बताया कि पहली बार आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 579 प्रतिभागी (271 महिला और 308 पुरुष) भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में 100, 200 और 400 मीटर दौड़, लंबी व ऊंची कूद, शॉटपुट, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी और खो–खो सहित कुल 13 खेलों में प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता 22 फरवरी तक चलेगी।

संक्षिप्त

पेड़ से लटकता मिला युवती का शव

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर के बाहर नीम के पेड़ से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यह घटना बंथरा के मवई पड़ियाना गांव की है। यहां मजदूर राजेश गौतम की 20 वर्षीय बेटी बिंदु गौतम हाईस्कूल की पढ़ाई के बाद घर पर ही रहती थी। गुरुवार रात घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 5.30 बजे गांव की एक महिला ने राजेश के घर के सामने नीम के पेड़ पर बिंदु का शव दुपट्टे के सहारे लटकता देखा। महिला ने तुरंत इसकी जानकारी परिजनों को दी।

गांजा बेचने का विरोध किया तो पीट-पीटकर पुजारी की हत्या, गड्ढे में शव फेंका

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। उनका शव मंदिर के पीछे करीब 20 फीट गड्ढे में मिला। माथे पर चोट के निशान थे। गला घोंटा गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी। घटना दुबग्गा इलाके के आश्रयहीन कॉलोनी में 19 फरवरी की रात की है। पुजारी की पहचान 60 वर्षीय कल्लू प्रजापति उर्फ कल्लू बाबा के रूप में हुई है। वह कॉलोनी के शीतला माता मंदिर में करीब 40 साल से रहकर पूजा–पाठ करते थे। एस–2 आश्रयहीन कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गोलू ने शीतला माता मंदिर के पास गड्ढे में कल्लू बाबा का शव देखा। उन्होंने इसकी कॉलोनी के लोगों और पुलिस को सूचना दी।

नक्सल प्रभावित सुकमा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

आकांक्षा प्रोजेक्ट के तहत 35 युवा रोजगार हेतु चेन्नई रवाना

बीएनई

रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले सुकमा जिले से आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 35 युवा (16 युवतियां एवं 19 युवक) प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने हेतु चेन्नई के लिए रवाना हुए। यह अवसर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में संचालित प्रयासों का परिणाम है। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में संचालित 'आकांक्षा – सशक्त युवा, सशक्त सुकमा' कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित युवाओं को लाइवलीहुड कॉलेज परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर युवाओं में उत्साह, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।

एमओयू के माध्यम से रोजगार के अवसर

जिला प्रशासन ने निजी क्षेत्र में रोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चेन्नई स्थित ड्राइव मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ एक विशेष एमओयू किया है। इस साझेदारी के माध्यम से सुदूर अंचलों के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल उन युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है, जिन्हें अब तक अवसरों की सीमित उपलब्धता के कारण प्रतिस्पर्धात्मक मंच नहीं मिल पाता था।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

चयनित युवाओं में 16 युवतियों की भागीदारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह पहल न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है। पहली बार जिले से बाहर रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलने से युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना सुदृढ़ हुई है। कलेक्टर अमित कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'आकांक्षा – सशक्त युवा, सशक्त सुकमा' कार्यक्रम केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि सुकमा का प्रत्येक युवा कौशलयुक्त बने और उसे आजीविका के लिए श्रेष्ठ मंच प्राप्त हो। ग्राम आसिरगुड़ा, कोंटा निवासी सोड़ी बसंती ने बताया कि यह उनके जीवन का गौरवपूर्ण क्षण है। पहली बार घर से बाहर जाकर रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिला है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सकेंगी। बोरगुड़ा निवासी सोनिया नुप्पो ने जिला प्रशासन की इस पहल को सराहनीय बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि सुकमा जिला प्रशासन भविष्य में भी रोजगार मेलों, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उद्योग साझेदारियों के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्र की पहचान से आगे बढ़कर सुकमा को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अवसरों से परिपूर्ण जिले के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर, लाइवलीहुड कॉलेज के प्रभारी अधिकारी कैलाश कश्यप सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आईएएस अधिकारियों का सिगोड़ी हैंडलूम क्लस्टर का भ्रमण

बीएनई

पटना। विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग से प्रोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए आईएएस अधिकारियों ने आज पटना जिले के सिगोड़ी स्थित हैंडलूम क्लस्टर का एक्सपोज़र विज़िट किया। इस भ्रमण का उद्देश्य अधिकारियों को जमीनी स्तर पर औद्योगिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराना था। अधिकारियों को अंकित कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पटना, तथा अमन ,क्लस्टर विकास कार्यकारी (CDE), सिगोड़ी द्वारा उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं हैंडलूम क्षेत्र को प्रदान की जा रही सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण में वित्तीय सहायता, विपणन समर्थन, कौशल उन्नयन, क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं आधारभूत संरचना समर्थन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने हैंडलूम की कार्यप्रणाली को निकट से देखा तथा बुनकरों से संवाद कर उनकी उत्पादन प्रक्रिया, चुनौतियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अधिकारियों ने अज़हर अंसारी, अध्यक्ष, प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, तथा उद्योग विस्तार पदाधिकारी शिवशंकर से भी संवाद किया और क्लस्टर के संचालन, बुनकरों की समस्याओं एवं विभागीय सहयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों ने परंपरागत शिल्प के संरक्षण एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में क्लस्टर आधारित विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। यह एक्सपोज़र विज़िट प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ।

भारत का आर्थिक ढांचा अस्थिर वित्तीय बाजारों के बीच स्वस्थ और मजबूत, बोले आरबीआई गवर्नर

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक के दौरान कहा कि अस्थिर वित्तीय बाजारों के बावजूद मध्यम अवधि में भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत स्वस्थ और मजबूत बने हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में हुई बैठक में एमपीसी के सभी सदस्यों ने नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के मिनट्स के अनुसार, गवर्नर सहित अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि वर्तमान वृद्धि–मुद्रास्फीति की गतिशीलता को देखते हुए मौजूदा दर उचित है। एमपीसी की बैठक, जो 4 से 6 फरवरी तक आयोजित हुई, में अल्पकालिक उधार दर (रेपो दर) को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया। बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव और व्यापारिक टकरावों से उत्पन्न भारी चुनौतियों के बावजूद, प्रौद्योगिकी से संबंधित निवेशों में उछाल, अनुकूल राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के समर्थन से, वैश्विक विकास 2026 में मामूली रूप से अधिक रहने की उम्मीद है, मल्होत्रा के हवाले से कार्यवाही में यह बात कही गई है। विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति के परिणाम भिन्न–भिन्न रह सकते हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने राहत चक्रों के अंत के करीब पहुंचने पर अलग–अलग नीतिगत रास्ते अपनाने की संभावना है, उन्होंने आगे कहा। मल्होत्रा ने आगे कहा, ष्बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और भू–राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल में, वैश्विक निवेशकों की भावनाएं घबराई हुई हैं और वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, बाह्य क्षेत्र सहित मध्यम अवधि में भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत स्वस्थ और मजबूत बने हुए हैं, और मुद्रास्फीति–विकास की गतिशीलता के संदर्भ में, ष्हम पिछली नीति की तुलना में समान या थोड़ी बेहतर स्थिति में हैंष्। उन्होंने कहा कि विकास की संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं जबकि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना हुआ है, और बाहरी मोर्चे पर हाल के कई घटनाक्रमों ने अधिक आशावाद के लिए गुंजाइश प्रदान की है।

संक्षिप्त

दिल्ली मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे विजेंदर सिंह और रोहन बोपन्ना, रविवार को होगा आगाज

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह और देश के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली मैराथन के 11वें एडिशन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मैराथन में 30,000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) से प्रमाणित, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसश से मान्यता प्राप्त और विश्व एथलेटिक्स से स्वीकृत यह मैराथन वैश्विक एथलेटिक कैलेंडर में अपनी जगह मजबूत कर रही है। इस चरण में 31 देशों, 490 शहरों और भारत के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग हिस्सा लेंगे जिसका आयोजन चार वर्ग फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10के और 5के में किया जाएगा भारत का प्रतिनिधित्व एक एलीट टीम करेगी जिसमें अनीश थापा, एबी बेलियप्पा, मान सिंह, अक्षय सैनी, टी गोपी, भागीरथी बिष्ट, निरमाबेन ठाकोर भारतजी, अश्विनी मदन जाधव, डिस्केट डोलमा और स्टैंजिन डोलकर शामिल हैं। यह मैराथन आने वाले एशियाई खेलों के लिए एक क्वालीफाइंग रेस भी है।

एनसीएल की निगाही परियोजना ने सीएसआर के तहत वार्ड क्रमांक 24 में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

150 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का उठाया लाभ

बीएनई

सिंगरौली। एनसीएल द्वारा सीएसआर के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से समय–समय पर अनेक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है, इसी क्रम में गत गुरुवार को एनसीएल की निगाही परियोजना ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत वार्ड क्रमांक 24, नवानगर में निरूशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान निगाही परियोजना से चिकित्सकों की टीम ने उपस्थित लोगों के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया। इस अवसर पर 150 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवा कर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया जिसमें 30 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि एनसीएल, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे शिविरों का आयोजन करता रहता है ताकि समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।

वापसी करने पर होंगी भारतीय हॉकी टीम की नजरें, स्पेन के खिलाफ मैच के साथ होगी होबार्ट चरण की शुरुआत

बीएनई

होबार्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम घरेलू मैदान पर बुरी तरह हारने के बाद शनिवार को स्पेन के खिलाफ मैच के साथ एफआईएच प्रो लीग के विदेशी चरण की शुरुआत करेगी। टीम नए कप्तान हार्दिक सिंह के नेतृत्व में वापसी करने और एक नई शुरुआत करने के लिए बेताब होगी। सीरीज का होबार्ट चरण 25 फरवरी तक तस्मानिया हॉकी सेंटर में होगा जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत को अर्जेंटीना और बेल्जियम से मिली थी हार हाल में राउरकेला चरण भारतीयों के लिए सीखने का दौर साबित हुआ जिसमें उन्हें अर्जेंटीना और बेल्जियम से हार मिली। नियमित कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए आने वाले मैचों से ब्रेक लिया है। टीम इन मुकाबलों को आने वाले एफआईएच विश्व कप और उसके बाद के एशियाई खेलों से पहले संयोजन को परखने और लय बनाने के एक जरूरी मौके के तौर पर देख रही है। स्पेन के खिलाफ पहले मैच के बाद रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होना है। 24 फरवरी को उनका सामना फिर स्पेन से होगा और 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ अंतिम मैच के साथ यह चरण खत्म होगा। भारत और स्पेन के बीच पिछले 10 मैच का रिकॉर्ड भारत और स्पेन अपने पिछले 10 मुकाबलों में बराबरी पर रहे हैं, दोनों ने नियमित समय में चार–चार जीत हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार हाई–स्कोरिंग ड्रामा रहा है। मेजबान टीम अपने पिछले 10 मुकाबलों में

छह जीत और दो ड्रॉ के साथ बढ़त बनाए हुए है। दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हार्दिक उस टीम को अगुआई करेंगे जिसमें अमनदीप लाकड़ा और मनमीत सिंह जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं। अंगद बीर सिंह, अराजित सिंह हुंडाल और आदित्य अर्जुन लालागे जैसे उभरते हुए स्टार भी फॉरवर्ड लाइन में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब होंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूपी निर्णायक छलांग की ओर

बजट की घोषणाओं से प्रदेश बनेगा टेक्नोलॉजी पावरहाउस
एआई मिशन और डेटा सेंटर क्लस्टर से डिजिटल गवर्नेंस को नई मजबूती
टेक्नोलॉजी मिशन और सैटेलाइट सेंसर से विज्ञान आधारित विकास को रफ्तार

संवाददाता

लखनऊ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निर्णायक छलांग लगाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र को और गतिशील बनाने के लिए योगी सरकार ने बजट 2026–27 के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं आईटी क्षेत्र को नई दिशा देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की है। इस पहल से प्रदेश न केवल डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और नवाचार का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। बजट में इंडिया एआई मिशन और इंडिया एआई डेटा लैब को आगे बढ़ाने के साथ उत्तर प्रदेश एआई मिशन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित समाधान विकसित करना है। उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर को सुदृढ़ कर प्रदेश को सुरक्षित डेटा भंडारण और क्लाउड सेवाओं का बड़ा हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू–हब की स्थापना से स्टार्टअप और नवाचार को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन हब के माध्यम से युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन, मेंटरशिप और निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे। टेक युवा समर्थ युवा योजना के तहत तकनीकी क्षेत्र में दक्ष युवाओं को प्रोत्साहन देकर उन्हें रोजगार, कारोबार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ कर योगी सरकार डिजिटल

युग की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। यूपी स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क–3 के विस्तार से शासन की डिजिटल कनेक्टिविटी और तेज होगी। इससे जिला और तहसील स्तर तक ऑनलाइन सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।प्रदेश में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण और वर्तमान संस्थानों के उच्चीकरण से तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पत्नी के जन्मदिन पर राजकुमार राव ने लुटाया प्यार, अनदेखी तस्वीरें शेयर कर लिखी प्यारी पोस्ट

एजेंसी

हाल ही में राजकुमार राव अपने लुक की वजह से चर्चा में आ गए। इस पर उन्होंने सफाई दी है। इस बीच अभिनेता ने अपनी पत्नी पत्रलेखा को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं और एक प्यार भरी पोस्ट लिखी है। आइए जानते हैं इसमें क्या है? पत्नी के साथ राजकुमार राव राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में दोनों दूल्हा–दुल्हन के रूप में नजर आ रहे हैं। कई दूसरी तस्वीरों में वह अपनी पत्नी के साथ सैर पर निकले हैं। एक और तस्वीर में अभिनेता अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे हैं। राजकुमार राव ने लिखी प्यारी पोस्ट राजकुमार राव ने अपनी पत्नी को लेकर पोस्ट में लिखा है श्माय लव आपको जन्मदिन की बधाई। तुम मेरी सबसे अच्छी चीज हो। तुम मेरे घर का दिल हो। मैं और पार्वती बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम हमारी जिंदगी में हो। तुम सबसे अच्छी पार्टनर, सबसे अच्छी मां और सबसे अच्छी बेटी हो। तुम जैसी सबसे अद्भुत महिला को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। सेलेब्स ने किए कमेंट राजकुमार राव की पोस्ट को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं। इस पर कई सेलेब्स ने कमेंट किए हैं। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए दिल वाले इमोजी बनाए हैं। वहीं भूमि पेडनेकर ने पत्रलेखा को टैग करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। राजकुमार राव और पत्रलेखा का रिश्ता आपको बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 वर्षों तक एक–दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। दोनों ने 2021 में शादी की। नवंबर 2025 में दोनों ने अपने पहले बच्चे पार्वती का स्वागत किया। नए लुक पर प्रतिक्रिया हाल ही में राजकुमार राव एक इवेंट में नए लुक में नजर आए। उनके फैंस ने उनके भरे चेहरे और कम बालों को लेकर चिंता जाहिर की।

विश्व बैंक ने किया विशेष फंड का एलान, अजय बंगा ने बताई भूमिका, जानिए सबकुछ

एजेंसी

नई दिल्ली। युद्ध प्रभावित गाजा के पुनर्निर्माण को गति देने के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने एक समर्पित गाजा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। यह फंड अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मिलने वाले धन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करेगा और पुनर्निर्माण परियोजनाओं में उसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगा। बोर्ड ऑफ पीस का फंड विश्व बैंक के भीतर स्थापित हो चुका है वाशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक को संबोधित करते हुए बंगा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पारित होते ही विश्व बैंक ने फंड की स्थापना की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि यह फंड अब विश्व बैंक के भीतर स्थापित हो चुका है और दानदाताओं से मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व बैंक की क्या होगी भूमिका? बंगा ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था में विश्व बैंक लिमिटेड ट्रस्टी की भूमिका निभाएगा, जबकि फंड का संचालन नवगठित बोर्ड ऑफ पीस के निर्देशों के तहत किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी प्रणाली का आधार पारदर्शिता और जवाबदेही होगी,

ताकि सहयोग देने वाले देशों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि उनका धन किस परियोजना और किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय, कानूनी और निगरानी से जुड़े कड़े मानक लागू किए जाएंगे। साथ ही जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए विश्व बैंक ने एक वित्तीय नियंत्रक को प्रतिनियुक्ति पर बोर्ड ऑफ पीस के साथ जोड़ा है। विश्व बैंक की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं विश्व बैंक समूह की व्यापक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बंगा ने तीन प्रमुख प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। पहला, सार्वजनिक वित्त का अधिकतम उपयोग, जिसमें विश्व बैंक की उच्च क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से निजी बांड के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावना शामिल है। दूसरा, निजी निवेश को जोखिम से मुक्त बनाना, जिसके तहत गारंटी और वित्तीय उपकरणों के जरिए निजी पूंजी को आकर्षित किया जाएगा। तीसरा, विश्व बैंक की जमीनी विशेषज्ञता और अनुभव, जिसका उपयोग गाजा के पुनर्निर्माण कार्यों में किया जाएगा। विश्व केवल दूर से निगरानी करने वाली संस्था नहीं रहेगा उन्होंने कहा कि विश्व बैंक केवल दूर से निगरानी करने वाली संस्था नहीं रहेगा, बल्कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएगा, ताकि गाजा और पूरे क्षेत्र के लोगों को बेहतर जीवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बैठक में प्रस्तुत पुनर्निर्माण योजना में आवास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण का खाका शामिल है। इसके अलावा गाजा में नई फिलिस्तीनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कई देशों ने अरबों डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 10 अरब डॉलर तक की सहायता का वादा शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व बैंक की भागीदारी से गाजा के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को एक संगठित, पारदर्शी और संस्थागत वित्तीय ढांचा मिला है, जिसे हाल के वर्षों की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पहलों में से एक माना जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743